



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

## PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2015/ज्येष्ठ 28, 1937

No. 163]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2015/JYAISTHA 28, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिवेशालय)

जाँच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2015

**विषय :-**चीन जन. गण. , इरान, इण्डोनेशिया, मलेशिया, और ताईवान मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित प्योरीफाइड टैरेफ्टैलिक एसिड (पीटीए) के आयातो से सम्बंधित पाटनरोधी जाँच की शुरुआत।

**सं. 14/8/2015—डीजीएडी.**—यह: समय—समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसके अंतर्गत बने समय—समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए; मैसर्स एमसीसी पीटीए इंडिया कार्प प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन चीन जन. गण. , इरान, इण्डोनेशिया, मलेशिया, और ताईवान (जिन्हें एतदपश्चात सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित प्योरीफाइड टैरेफ्टैलिक एसिड (जिसे एतदपश्चात सम्बद्ध वस्तु या पीटीए कहा गया है) के आयातों से सम्बंधित पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करने के लिए संयुक्त रूप से दायर किया है।

**2.** और यह: प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि सम्बद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के पाटन होने, घरेलू उद्योग को 'क्षति' होने, तथा पाटन एवं क्षति के बीच अभिकथित कारणात्मक संबंध होने के प्रथम दृष्ट्या साक्ष हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करने को चाचोचित ठहराते हैं। इसलिए प्राधिकारी एतदद्वारा किसी अभिकथित पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जाँच करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अन्तर्गत एक जाँच की शुरुआत करते हैं जो अभिकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और उसके प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की एक एसी राशि की सिफारिश करने, जो यदि उद्ग्रहित की गई तो, घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पूर्णपात होगी।

## घरेलू उद्योग एवं आधार

**3.** यह आवेदन पत्र घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स एमसीसी पीटीए इंडिया कार्प प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया है। उपर्युक्त घरेलू उत्पादकों के अतिरिक्त, भारत में पीटीए का एक अन्य उत्पादक भी है अर्थात इण्डियन आयल

कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल)। मैसर्स आई ओ सी एल ने इस आवेदन का समर्थन किया है। मैसर्स एमसीसी पीटीए इण्डिया कार्प प्राइवेट लिमिटेड ने एक घोषणा यह उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की है कि उन्होंने इस विचाराधीन उत्पाद का सम्बद्ध देशों से आयात नहीं किया है। उन्होंने पुनः यह घोषणा की है कि उनका सम्बद्ध देशों में इस विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक या निर्यातक उथवा भारत में उसे विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से कोई सम्बंध नहीं है। तथापि, सह आवेदक रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने एक घोषणा यह उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की है कि उन्होंने इस सम्बद्ध वस्तु का मलेशिया से भारी मात्रा में आयात अग्रिम प्राधिकृतीकरण स्कीम के अन्तर्गत मलेशिया के एक असम्बद्ध व्यापारी के माध्यम से किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनकी मलेशिया में इस सम्बद्ध वस्तु के एक एकल उत्पादक के रूप में एक एसोसिट कम्पनी और मलेशिया में एक अनुषंगी कम्पनी भी है जिसने जाँच की अवधि के दौरान भारत को इस सम्बद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

4. और यह: मैसर्स एमसीसी पीटीए इण्डिया कार्प प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की मलेशिया में में एक अनुषंगी कम्पनी है जिसने जाँच की अवधि के दौरान इस सम्बद्ध वस्तु का भारत को भारी मात्रा में निर्यात किया है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अन्तर्गत रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को घरेलू उद्योग के रूप में मानना उपयुक्त नहीं समझते हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि मैसर्स एमसीसी पीटीए इण्डिया कार्प प्राइवेट लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात आवेदक भी कहा गया है) पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के आशय के अन्तर्गत एक घरेलू उद्योग है और उसे पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानते हैं और यह आवेदन पत्र, मैसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का अपवर्जन कर देने के पश्चात पूर्वोक्त नियमावली के नियम 5(3) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार आधार के मानदण्डों को पूरा करता है। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, प्राधिकारी ने मैसर्स एमसीसी पीटीए इण्डिया कार्प प्राइवेट लिमिटेड के सम्बंध में प्रस्तुत आंकड़ों/सूचना का प्रथम दृष्ट्या अपेक्षित क्षति विश्लेषण किया है।

### विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) प्योरीफाइड टैरेपथैलिक एसिड(पीटीए), अपने सभी प्राकारान्तरों – मीडियम क्वालिटी टैरेपथैलिक एसिड (एमटीए) और क्वालीफाइड टैरेपथैलिक एसिड (क्यूटीए) सहित है। प्योरीफाइड टैरेपथैलिक एसिड (पीटीए) एक सफेद फ्री फ्लोइंग क्रिस्टलाइन पाउडर है, जो किसी भी दृष्टिगोचर संदृश्य से मुक्त है। टैरेपथैलिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक फार्मूला सी6 एच4 (सी ओ ओ एच)2 होता है। यह 402 डिग्री सेल्सियस पर उर्ध्वपातित हो जाता है और यह जल एवं अल्कोहल में कम घुलनशील है। पीटीए पालिएस्टर चिप्स बनाने के लिए प्राथमिक कच्चा मात्र है जिसका टैक्सटाइल्स, पैकेजिंग, फर्निशिंग्स, उपभोक्ता वस्तुओं, रेजिन्स और कॉटिंग्स में कई अनुप्रयोग हेतु प्रयोग किया जाता है। चूंकि क्यूटीए, एमटीए और पीटीए रासायनिक रूप से सामान उत्पाद हैं और चूंकि उनका प्रयोग अंतर्निमेय रूप से किया जाता है इसलिए इस विचाराधीन उत्पाद के दायर में क्यूटीए और एमटीए को भी शामिल किया जाता है। आवेदकों द्वारा किए गए दावे के अनुसार डाइ-मिथाइल टैरेपथैलेट (डीएमटी) रासायनिक रूप से एक भिन्न उत्पाद है और इसलिए यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है। विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के उपशीर्षक संख्या 29173600 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जाँच के दायरे के अंतर्गत बाध्यकारी नहीं है।

### समान वस्तु

6. आवेदकों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु तथा सम्बद्ध देशों से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अन्तर नहीं है। आवेदक द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्योरीफाइड टैरेपथैलिक एसिड तथा संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु गुणधर्मों जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय हैं। आवेदक ने पुनः यह दावा किया है कि दोनों ही तकनीकी रूप से एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए उन्हें नियमावली के अन्तर्गत समान वस्तु के रूप में माना जाए। उपभोक्तागण इनका प्रयोग अंतर्निमेय रूप से कर सकते हैं और कर रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद का आयात करने वाले उपभोक्ताओं ने इसकी घरेलू उद्योग से खरीद भी की है। इसलिए वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद को नियमों के अनुसार घरेलू समान वस्तु के रूप में मानते हैं।

### सम्बद्ध वस्तु

7. वर्तमान जाँच में अन्तर्ग्रस्त देश चीन जन. गण. इरान, इण्डोनेशिया, मलेशिया और ताईवान हैं। वर्तमान जाँच में इन देशों का उल्लेख सम्बद्ध देश के रूप में किया जा रहा है।

### समान्य मूल्य

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के संलग्नक-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाए। आवेदक ने चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का दावा भारत में विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर किया है। नियमावली के संलग्नक-1 के पैरा 8 के अनुसार यह प्रकल्पना की जाती है कि चीन जन. गण. में सम्बद्ध वस्तु के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए चीन जन. गण. के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना और उसका चीन जन. गण. के प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अध्यधीन चीन जन. गण. में सम्बद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का आकलन नियमावली के संलग्नक-1 के पैरा-7 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार किया गया है। जहाँ तक इरान, इण्डोनेशिया, मलेशिया और ताईवान का सम्बद्ध है आवेदक ने यह प्रस्तुत किया है कि इन देशों में घरेलू कीमतों के साक्ष प्राप्त करने के सर्वोत्तम प्रयास किए गए परन्तु फिर भी वे सभी प्रयास इन देशों में सम्बद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के सम्बंध में कोई विश्वसनीय सूचना या दस्तावेजी साक्ष प्राप्त करने में असफल रहे। आवेदक ने इरान, इण्डोनेशिया, मलेशिया और ताईवान में इन देशों के सम्बंध में सामान्य मूल्य का दावा प्रमुख कच्चे माल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों का समायोजन करने के पश्चात भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया है।

### **निर्यात कीमत**

9. आवेदक द्वारा निर्यात कीमत का दावा डीजीसी आई एण्ड एस से प्राप्त आयात आंकड़ों से सम्बद्ध देशों की भारित औसत आयात कीमत के रूप में किया गया है। निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, कमीशन, अन्तर्राष्ट्रीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभार के सम्बंध में कीमत समायोजन किया गया है।

### **पाटन मार्जिन**

10. सामान्य मूल्य की तुलना फैक्ट्री बाह्य स्तर पर निर्यात कीमत से की गई इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है कि सम्बद्ध देशों में सम्बद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य फैक्ट्री बाह्य निर्यात कीमत से अधिक है, इससे यह संकेत मिलता है कि सम्बद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में सम्बद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। आकलन किया गया पाटन मार्जिन न्यूनतर से अधिक है।

### **क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

11. घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने इन पाटित आयातों की संबंधित भारी मात्रा के रूप में समग्र रूप से और भारत में खपत एवं उत्पादन के संगत रूप से अधिकसित पाटन के परिणामस्वरूप में हो रही असिक्तिक्षति, कीमत निग्रहण, कीमत अधोविक्रयण के सम्बंध में और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को लाभ, नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ तथा नकदी प्रवाह के रूप में विपरीत प्रभाव के पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इन संबद्ध देशों से हो रहे पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को कारित की जा रही क्षति के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य इस पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोदित ठहराते हैं।

### **जाँच की अवधि**

12. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 (12 माह) है। तथापि, क्षति जाँच अवधि के लिए अप्रैल 2011—मार्च 2012, अप्रैल 2012—मार्च 2013, अप्रैल 2013—मार्च 2014 तथा जाँच की अवधि को अवधि के रूप में विचार किया गया है।

### **शुल्क का पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिरोपण**

13. आवेदक ने शुल्क का अधिरोपण प्रवर्वव्यापी प्रभाव से करने का अनुरोध किया है क्योंकि घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति सम्बद्ध उत्पाद के काफी पिछले समय से भारी पाटन द्वारा कारित की गई है। उन्होंने पुनः यह प्रस्तुत किया है कि इन आयातों की भारी मात्रा और घरेलू उद्योग को क्षति पर विचार करते हुए, जब तक इस शुल्क का पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिरोपण करने की सिफारिश नहीं की जाती है तब तक पाटनरोधी शुल्क के वांछित उपचारी उपाय पूरे नहीं कहे जा सकेंगे। हितबद्ध पक्षकार इस सम्बंध में अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।

### **सूचना प्रस्तुत करना**

14. सम्बद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों तथा सम्बद्ध देशों की सरकार को भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए और भारत में इस संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप और ढंग से सभी संगत जानकारी दर्ज करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत करने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है :

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**  
**वाणिज्य विभाग**  
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग**  
**नई दिल्ली—110001**

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी उल्लिखित समय सीमा के अंदर विहित स्वरूप और ढंग से जाँच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है।

### **समय—सीमा**

16. वर्तमान जाँच से संबंधित किसी सूचना को और सुनवाई के लिए किसी अनुरोध को लिखित रूप में इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे कि वह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से (40 दिनों) से अनधिक समय में पहुँच जाए। यदि निर्धारित समय—सीमा के अन्दर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

17. वर्तमान मामले में सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें और घरेलू उद्योग के आवेदनपत्र पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के अंदर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

### **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

18. प्रश्नावली पत्युत्तर/प्रस्तुतीकरण के किसी भाग पर यदि गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो पृथक सेटों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए (क) गोपनीय के रूप में (शीर्षक, अनुक्रमणिका, पृष्ठों की संख्या आदि सहित) के रूप में विनिहत तथा (ख) दूसरा सेट अगोपनीय (शीर्षक, अनुक्रमणिका, पृष्ठों

की संख्या आदि सहित) के रूप में चिन्हित होना चाहिए। प्रस्तुत की गई सभी सूचना को स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर चिन्हित किया जाना चाहिए।

**19.** किसी गोपनीय चिन्हांकन के बिना की गई प्रस्तुति को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय के रूप में समझा जाएगा और प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि ऐसी प्रस्तुतिकरण का निरीक्षण करने के लिए वह अन्य इच्छुक पक्षकारों को अनुमति प्रदान करें। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**20.** 'गोपनीय' के रूप में दावा की गई सूचना के साथ उन कारणों का विवरण प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है कि उक्त सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/अथवा उक्त सूचना को संक्षेप में प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

**21.** अगोपनीय संस्करण सूचना अनुक्रमित अथवा रिक्त किए गए और जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया हो, के आधार पर सार रूप में की गई गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सार इतने विस्तृत रूप में हो कि उससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि उसका सार प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

**22.** प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए किया गया अनुरोध वांछित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता उस सूचना को सार्वजनिक करने का इच्छुक नहीं है या उसका सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करना नहीं चाहता है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

**23.** सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता की दावे के संबंध में सद्कारण के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने पर और उसे स्वीकार कर लिए जाने पर प्राधिकारी ऐसी सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकार द्वारा विशेष रूप में प्राधिकृत किए बिना किसी भी पक्षकार को उस सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

#### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

**24.** पाटनरेधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुरूप कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

#### **असहयोग**

**25.** यदि कोई हितबद्ध पक्षकार किसी सूचना की पहुंच तक मनाही करता है और युक्तिसंगत अवधि के अंदर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में भारी व्यवधान उत्पन्न करता है तो प्राधिकारी ऐसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगकर्ता पक्षकार के रूप में घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को समुचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. के. दाटू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

#### **MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)**

#### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2015

**Subject:—Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of Purified Terephthalic Acid (PTA), originating in or exported from China PR, Iran, Indonesia, Malaysia & Taiwan.**

**No. 14/8/2015-DGAD.**—Whereas M/s MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd., and M/s Reliance Industries Limited jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Purified Terephthalic Acid (hereinafter also referred to as the subject goods or PTA), originating in or exported from China PR, Iran, Indonesia, Malaysia & Taiwan (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. And whereas, the Authority finds existence of prima facie evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' to justify initiation of an anti-dumping investigation; the

Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

#### **Domestic Industry & Standing**

3. The Application has been filed by M/s MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd and M/s Reliance Industries Limited on behalf of the domestic industry. Apart from the above domestic producers there is one more producer of PTA in India, namely Indian Oil Corporation Limited (IOCL). M/s IOCL has supported the present application. M/s MCC PTA India Corp. Private Limited has furnished a declaration stating that they have not imported the PUC from the subject countries. They have further declared that they are not related either to any exporter or producer of the PUC in the subject countries or any importer of the PUC in India. However, the co-applicant i.e. Reliance Industries Ltd furnished a declaration stating that they have imported insignificant volume of subject goods from Malaysia through an unrelated Malaysian trader under Advance Authorization Scheme. They further declared that they have an associate company in Malaysia as the sole producer of the subject goods in Malaysia and also a subsidiary company in Malaysia who exported the subject goods to India during the POI.
4. And whereas, on the basis of examination of the information furnished by M/s MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd., and M/s Reliance Industries Limited, the Authority notes that M/s Reliance Industries Ltd has a subsidiary company in Malaysia which has exported significant volume of subject goods to India during the POI. In view of the above position, the Authority does not consider it appropriate to accept Reliance Industries Ltd as an eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules. Further, the Authority holds that M/s MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd (hereinafter also referred to as the applicant) constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-dumping Rules as eligible domestic industry and the application, after excluding M/s Reliance Industries Ltd, satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra. In view of this position, the Authority has made the required *prima facie* injury analysis by taking the data/information furnished in respect of M/s MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd., only.

#### **Product under Consideration**

5. The Product under Consideration (PUC) in the present investigation is Purified Terephthalic Acid (PTA), including its variants - Medium Quality Terephthalic Acid (MTA) and Qualified Terephthalic Acid (QTA). The PUC is a white, free flowing crystalline powder, free from any visual contamination. Terephthalic Acid is an organic compound whose chemical formula is  $C_6 H_4 (COOH)_2$ . It sublimes at 402°C and is poorly soluble in water and alcohol. PTA is primary raw material in the manufacture of polyester chips which in turn is used in a number of applications in textile, packaging, furnishings, consumer goods, resins and coatings. Since QTA, MTA and PTA are chemically the same product and further since they are interchangeably used, the scope of the product under consideration covers QTA and MTA as well. The applicant has further claimed that Di-Methyl Terephthalate (DMT) is chemically a different product and therefore not covered in the scope of the product under consideration. The product under consideration is classified under subheading 29173600 of the Customs Tariff Act. However, the customs classification is indicative only and in no way it is binding on the scope of the present investigation.

#### **Like Article**

6. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the applicants. As submitted by the applicant, the Purified Terephthalic Acid (PTA) produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The applicant has further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation,

the Authority treats the subject goods produced by the applicant in India as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries/territories.

#### **Subject Countries**

7. The countries involved in the present investigation are China PR, Iran, Indonesia, Malaysia & Taiwan. These are being referred to as the subject countries in the present investigation.

#### **Normal value**

8. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and determined normal value in accordance with Paras 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The applicant has claimed normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from China PR, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules. As regards Iran, Indonesia, Malaysia & Taiwan the Applicant has submitted that best possible efforts were made to procure evidences of domestic price in these countries, but however they were unable to get any documentary evidence or reliable information with regard to the domestic prices of the subject goods in these countries. The applicant has claimed the normal value in respect of Iran, Indonesia, Malaysia & Taiwan on the basis of cost of production in India after due adjustments for the international price of the major raw materials.

#### **Export Price**

9. The export price has been claimed by the applicants as the weighted average import price from subject countries based on the import data obtained from the DGCIS. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges to arrive at the net export price.

#### **Dumping Margin**

10. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margins are estimated to be above de minimis.

#### **Injury and Causal Link**

11. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price suppression, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of profits, return on capital employed, and cash flow to the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of the ‘injury’ being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

#### **Period of Investigation (POI)**

12. The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is from 1<sup>st</sup> April 2014 to 31<sup>st</sup> March 2015 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from April 2011 - March 2012, April 2012 - March 2013, April 2013 - March 2014 and the POI.

#### **RETROSPECTIVE IMPOSITION OF DUTIES**

13. The applicant has requested for retrospective imposition of duty as the injury is claimed to be caused to the domestic industry by a history of massive dumping of subject product. They have further submitted that considering the huge volume of such imports and injury to the domestic industry, unless duty is

recommended retrospectively, the desired remedial measures of anti-dumping duties may not be accomplished. The interested parties may make their submissions in this regard.

### **Submission of Information**

14. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,**  
**Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,**  
**Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce**  
**4<sup>th</sup> Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,**  
**New Delhi -110001.**

15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below

### **Time Limit**

16. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.
17. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

### **Submission of information on confidential basis**

18. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
19. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
20. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of public file**

24. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

25. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. K. DADOO, Designated Authority